राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा

गो ग्रीन पहल

विषय-सूची

1. पृष्ठभूमि ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. शहरी आवासीय परिदृश्य: 2

3. राष्ट्रीय आवास बैंक की गो-ग्रीन पहल 3

निम्न पर रा.आ.बैंक-केएफडब्ल्यू कार्यक्रम 3

"ऊर्जा दक्ष नये रिहायशी आवास" ..... **Error! Bookmark not defined.**

फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस के साथ करार के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हरित एवं किफायती आवास का संवर्द्धन ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. सनरेफ किफायती हरित आवास भारत कार्यक्रम 4

सनरेफ भारत के बारे में : ..... **Error! Bookmark not defined.**

कार्यक्रम की स्थिति ..... **Error! Bookmark not defined.**

प्रक्रिया प्रवाह तथा टीए से सहायता 8

फोटो गैलरी ..... **Error! Bookmark not defined.**

हमसे संपर्क करें ..... **Error! Bookmark not defined.**

गो ग्रीन पहल

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) भारत में आवास वित्त बाजार को नया आकार देने एवं इसके विकास में चार्टर के साथ-साथ एक सांविधिक निकाय है। वित्तीय प्रणाली (वित्तीय गहनता) का विकास एवं आर्थिक विकास परस्पर संबद्ध है। यह माना जाता है कि समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वित्तीय सेवाओं के वर्धित प्रावधान का बड़ी अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। वित्तीय गहनता अर्थव्यवस्था में चलनिधि की उपलब्धता के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा कमजोर एवं सुविधाहीन समूह को प्रभावशाली अर्थव्यवस्था में शामिल करने हेतु सहायता प्रदान करती है। इस आधार पर यह स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षाप्रद जैसी मूल सेवायें प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत एवं परिवारों की दक्षता बढ़ाने में मदद करती है, जिससे गरीबी में कमी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक अपने स्थापना काल से ही विभिन्न पुनर्वित्त एवं प्रत्यक्ष वित्त गतिविधियों के माध्यम से "श्रृंखला के सबसे निचले स्तर" (बीओपी) हेतु किफायती आवास वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। चूंकि किफायती वित्त की आवश्यकता वित्तीय प्रणाली के लिये सदैव महत्वपूर्ण रही है, रा.आ.बैंक ने अपनी विविध एवं सुलभ वित्तीय सेवाओं के माध्यम से निरंतर आवास क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान दिया है। रा.आ.बैंक देश में आवास वित्त की कमी के अंतर को कम करने के लिए नवीनतम कदम उठा रहा है तथा नई एवं मौजूदा योजनाओं और उत्पादों को विकसित कर रहा है। वर्षों के दौरान, बैंक ने देश में विद्यमान आवास की कमी को हल करने हेतु विशेष रूप से अनौपचारिक आय एवं संपत्ति के अनौपचारिक अधिकार के लोगों के लिए विभिन्न नवीनतम वित्तीय उत्पाद एवं साधन प्रदान किए हैं।

2. शहरी आवासीय परिदृश्य:

वर्ष 2030 तक, विश्व की 60% आबादी शहरों में बसी होगी। गांव से शहरी प्रवासन एवं जनसंख्या में साधारण वृद्धि ने अनियंत्रित एवं अनियोजित शहरीकरण को जन्म दिया है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की कमी में तेजी आई है एवं पर्यावरण प्रदूषित हुआ है।

शहर आज वैश्विक ऊर्जा खपत के दो-तिहाई एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। अरक्षणीय प्रथाएं एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन में प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो रही हैं तथा अपूरणीय क्षति हो रही है।

इस प्रकार, दुनिया भर के देश निम्न कार्बन फुटप्रिंट के साथ विकास की गति को तेज करने हेतु कार्य कर रहे हैं। सतत शहरीकरण संपूर्ण रूप से मानव विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की पर्यारणीय गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण है।
वैश्विक विकास के चरण में एक प्रमुख भागीदार के रूप में, भारत को निम्न-कार्बन विकास मॉडल में परिवर्तन करने के कारण अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है।

अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2030 तक, देश की 40% आबादी के शहरी क्षेत्रों में बसने का अनुमान है, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बढ़ते शहरी आवास एवं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घटते संसाधनों के साथ प्रवासन भारत के लिए वास्तविक एवं निरंतर चुनौती है।

सरकार के वर्ष 2012 के अनुमान के अनुसार, भारत का शहरी आवास घाटा 18.78 मिलियन (1.87 करोड़) इकाई है, जिसमें से 96% आर्थिक रूप से कमजोर (56%) एवं निम्न आय समूह (40%) से संबंधित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास विकल्प की कमी देश के विकास के मार्ग एवं गरीबी उन्मूलन प्रयासों में बाधा डाल सकती है।

भारत में किफायती आवास पहल देश के बढ़ते आर्थिक कार्यबल को लक्षित करती है एवं यह सामाजिक समानता तथा सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

साथ ही, बड़े स्तर पर इस तरह की आवास पहलों की पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सतत निर्माण रणनीतियों का संयोजन पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के साथ-साथ रहने की स्थिति में सुधार कर सकता है।

हरित एवं सतत भवन-निर्माण की एक लोकप्रिय धारणा को बदलना भी आवश्यक है कि यह अधिक कीमती है या केवल अमीर व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकता है। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए आवास सुविधापूर्ण जीवन स्तर के साथ टिकाऊ हो सकता है। किफायती आवास के साथ पर्यावरणीय स्थायित्व को एकीकृत करना भारतीय आवास क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे प्रवर्तकों, खरीदारों एवं बड़े स्तर पर, पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा।

3. राष्ट्रीय आवास बैंक की गो-ग्रीन पहल

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) बाजार के विभाजन के माध्यम से आवास एवं आवास वित्त क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में सबसे आगे रहा है तथा बैंक ने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ असेवित और अप्लसेवित क्षेत्रों पर प्राथमिक जोर दिया है। रा.आ.बैंक ने भारत में ऊर्जा दक्ष रिहायशी आवास एवं आवास की पहचान एक ऐसे खंड के रूप में की है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, डिजाइन, उत्पाद एवं संवर्धन और वितरण के विकास के मामले में रिहायशी आवास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

"ऊर्जा दक्ष नये रिहायशी आवास"
पर रा.आ.बैंक-केएफडब्ल्यू कार्यक्रम

रा.आ.बैंक ने केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ सहभागिता में आवास क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना शुरू किया। **यह देश में इस तरह से पहली पहल थी**। बैंक ने 2010-11 में रिहायशी क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्ष आवासीय पुनर्वित्त योजना का प्रारंभ किया।

इन निधियों का उपयोग विभिन्न प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा 380 करोड़ रु. (अनुमानित) की कुल ऊर्जा दक्ष इकाइयों हेतु 2000 आवास ऋणों के लिए किया गया था।
कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां:

- €50 मिलियन की संपूर्ण राशि का उपयोग
- ऋणों की सं.: 2,065
- प्रमाणित भवनों की सं.: 21,577 रिहायशी इकाईयां (162 टॉवर)
- ऊर्जा बचत: 1,864 एमडब्ल्यूएच/पी.ए.
- CO2 में कमी: 32,800 टी/पी.ए.

इसने ऊर्जा दक्ष आवास के संबंध में जागरूकता के स्तर में सुधार हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ कार्य करने के लिए रा.आ.बैंक का नेतृत्व किया, जैसा कि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस के साथ हमारी नवीनतम साझेदारी में स्पष्ट दिखता है।

फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस के साथ करार के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हरित एवं किफायत्त आवास का संवर्द्धन

फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) पर्यावरण वित्त के लिए समंवित दृष्टिकोण को विकसित करने, हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दृष्टिकोण को संयोजित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा वित्त का सतत उपयोग (सनरेफ) लेबल के तहत, एएफडी स्थानीय वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां हरित विकास का वित्तपोषण एक चुनौती है, पर्यावरणीय ऋण व्यवस्था के माध्यम से नवीकृत हरित निवेश के विकास का समर्थन करता है।

सार्वजनिक एवं निजी प्रवर्तकों की सूक्ष्म तथा मध्यम आकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय वित्तीय संस्थानों को तकनीकी सहायता एवं ऋण व्यवस्था प्रदान की जाती है।

सनरेफ ग्रीन फाइनेंसिंग लेबल के अंतर्गत, एएफडी ने अब तक 30 से अधिक विकासशील देशों में 70 से अधिक वित्तीय संस्थानों को 2.5 बिलियन यूरो से अधिक प्रतिबद्ध किया है।
वर्ष 2017 में, एएफडी ने यूरोपीय संघ (ईयू) के समर्थन से आवास वित्त में भारत के शीर्ष वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के साथ सहभागिता में सनरेफ किफायती हरित आवास भारत कार्यक्रम का शुभांरभ किया।

4. सनरेफ किफायती हरित आवास भारत कार्यक्रम

सनरेफ भारत के बारे में:

एएफडी ने यूरोपीय संघ (ईयू) के समर्थन से, आवास वित्त में भारत की शीर्ष वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के साथ साझेदारी में सनरेफ किफायती हरित आवास भारत कार्यक्रम शुरू किया।

इस कार्यक्रम में, बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों के पास हरित तथा किफायती आवास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण के अवसरों तक पहुंच होगी जिससे घर खरीदारों और आवास विकासक की वित्त पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्थायी और किफायती आवास से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर हितधारकों को भी सक्षम करेगा और सनरेफ भारत ने 12 मिलियन यूरो के यूरोपीय संघ के अनुदान के साथ ही 100 मिलियन यूरो की एएफडी ऋण व्यवस्था के माध्यम से रा.आ.बैंक को 112 मिलियन यूरो का वित्तपोषण प्रदान किया है। यूरोपीय संघ के अनुदान से, ऋण व्यवस्था के अंतिम उधारकर्ताओं के लिए ऋण लागत को कम करने के लिए निवेश अनुदान के रूप में 9 मिलियन यूरो का उपयोग किया जाएगा तथा 3 मिलियन यूरो की तकनीकी सहायता का उपयोग सुविधा उप परियोजना व्युत्पत्ति तथा प्रारंभिक जांच एवं क्षमता निर्माण आदि के विपणन हेतु किया जाएगा।

100 मिलियन यूरो की ऋण सुविधा बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से स्थानीय लेबल द्वारा प्रमाणित योग्य हरित निर्माण परियोजनाओं के आवास खरीदारों तथा विकासक को पुनर्वित्त प्रदान करके हरित आवास क्षेत्र को दीर्घकालिक किफायती वित्त पोषण उपलब्ध कराने में रा.आ.बैंक की सहायता करती है। आधी निधियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग को प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

भारत में एएफडी जनादेश के अनुसार, रा.आ.बैंक एवं एएफडी द्वारा परियोजना का उद्देश्य हरित किफायती आवास के विकास का समर्थन करके देश में आवास उद्योग के आकस्मिक विकास के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना है:

कार्यक्रम का उद्देश्य है-

- पर्यावरण पर आवास उद्योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करना
- कुशल निर्माण सामग्री के उपयोग के साथ हरित आवासीय घरों के विकास को प्रोत्साहित करके ऊर्जा तथा पानी के बिलों में बचत बढ़ाना
- भारत में हरित एवं किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ाना
- निम्न एवं मध्यम आय वाले समूहों को हरित किफायती आवास प्रदान करना

परियोजना के अपेक्षित परिणाम तथा प्रभाव:

- आवास उद्योग को प्रभावित करने हेतु ठोस प्रभाव पैदा करना,
- आवश्यक विनियमन उपायों के पूरक वाले हरे रंग की लेबलिंग के दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाना,
- हरित आवास उद्योग के पक्ष वाले कुछ राज्यों द्वारा विनियमन एवं सार्वजनिक नीतियों को अपनाना,
- निम्न आय वाले परिवारों हेतु हरित आवास को किफायती बनाना।
- ऊर्जा दक्षता, पानी के उपयोग और कच्चे माल के अनुकूलन उपयोग में सुधार के माध्यम से CO_2, पानी की खपत तथा अपशिष्ट उत्पादन के उत्सर्जन को कम करना।

  सनरेफ किफायती हरित आवास कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं सीमित सब्सिडी के माध्यम से निम्न आय वाले परिवारों को किफायती मूल्य पर हरित आवास प्रदान करने की संभावना को प्रदर्शित करना है।
  यह कार्यक्रम हरित आवास बाजार के साथ ही प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) जैसे आवास वित्त कंपनियों एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास विकासक तथा किफायती आवास प्रदान करने वाली सार्वजनिक एजेंसियों को समर्थन देने में रा.आ.बैंक की संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।

  सनरेफ भारत दो मौजूदा स्थानीय हरित आवास लेबल, एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग (गृह) तथा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) को बढ़ावा देकर आवास क्षेत्र में ऊर्जा एवं पर्यावरण दक्षता पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कार्यक्रम के तहत पात्र हरित रेटिंग प्रणाली है:

- आईजीबीसी हरित आवास प्रणाली-स्वर्ण और प्लेटिनम रेटिंग के साथ पूर्व-प्रमाणित/प्रमाणित और आईजीबीसी हरित किफायती आवास रेटिंग प्रणाली- स्वर्ण और प्लेटिनम रेटिंग के साथ पूर्व-प्रमाणित/प्रमाणित

- गृह रेटिंग प्रणाली- 4/5 स्टार रेटिंग के साथ किफायती आवास रेटिंग प्रणाली- पूर्व-प्रमाणन/प्रमाणन हेतु 4/5 स्टार रेटिंग एवं गृह के साथ पूर्व-प्रमाणन/प्रमाणन।

परियोजना दृष्टिकोण वित्त एवं प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त भारत में किफायती हरित आवास के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सभी प्रासंगिक हितधारकों की सामाजिक जागरूकता तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।

2025 तक यह अनुमान है कि 4000 परिवार अनुमानित 329,000 वर्ग मीटर नए रहने योग्य फ्लोर के निर्माण के माध्यम से बेहतर आवास स्थितियों हेतु सनरेफ आवास कार्याक्रम से लाभान्वित होंगे। यह परियोजना 20 आवासीय उप-परियोजनाओं को ग्रीन लेबल प्रमाणन का समर्थन करेगी।

सनरेफ इंडिया कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होने वाले परिवारों की कुल संख्या में से कम से कम 50% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवार होंगे शेष सुविधा मध्यम आय वर्ग को आवंटित की जाएगी।

भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, 3 लाख रूपये, 6 लाख रूपये तथा 18 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम-आय वर्ग की श्रेणियों में आते हैं।

प्रक्रिया प्रवाह का इकोसिस्टम नीचे दर्शाया गया है:

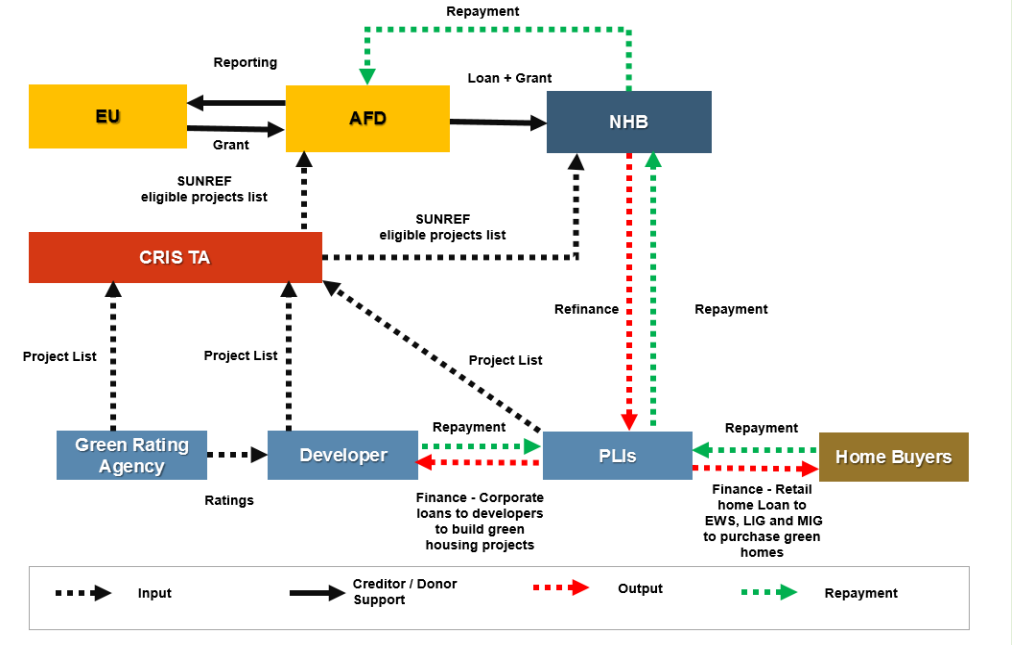

कार्यक्रम की स्थिति

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सनरेफ किफायती हरित आवास भारत कार्यक्रम के तहत 2 पुनर्वित्त योजनाएं तैयार की है तथा 15 सितम्बर, 2021 तक बैंक ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार सनरेफ कार्यक्रम के तहत 501 करोड़ रूपये का संवितरण किया है:

	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी (करोड़ में.)	एमआईजी (करोड़ में)	कुल करोड़ में
सुविधा के तहत अब तक का समेकित संवितरण	205	296	501
मूल्य द्वारा संरचना प्रतिशत	41%	59%	100%
घरेलू इकाइयों की संख्या	1361	1211	2572
इकाइयों द्वारा संरचना प्रतिशत	53%	47%	100%

सनरेफ किफायती हरित आवास भारत कार्यक्रम के ब्रोशर तथा पुनर्वित्त योजना के पूर्ण विवरण हेतु कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें -

ब्रोशर –

https://nhb.org.in/en/whats_new/sunref/

पुनर्वित्त योजनाएं –

https://nhb.org.in/wp-content/uploads/2016/10/PGHRS-2018-English.pdf

सितम्बर, 2021 तक, बैंक ने कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा सभी हितधारकों के बीच हरित आवास पर जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

क्रं.सं	कार्यक्रम तथा योग्यता निर्माण सत्र
1	दिल्ली राष्ट्रीय कार्यक्रम
2	मुंबई क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम
3	डेवलपर्स तथा आर्किटेक्ट्स हेतु प्रशिक्षण - राजस्थान
4	पीएलआई हेतु वेबिनार – 1
5	आईसीआईसीआई आ.वि.कं हेतु वेबिनार
6	उम्मीद आ.वि.कं. हेतु वेबिनार
7	आईआईएफएल हेतु वेबिनार
8	आवास फाइनेंसर्स हेतु वेबिनार
9	साटिन आ.वि.कं. हेतु वेबिनार

10	डेवलपर्स तथा आर्किटेक्ट्स हेतु प्रशिक्षण - पश्चिम बंगाल
11	एचडीएफसी लिमिटेड हेतु वेबिनार
12	चार पीएलआई हेतु वेबिनार – 2
13	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश हेतु प्रशिक्षण
14	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा हेतु प्रशिक्षण

उपरोक्त कार्यशाला/कार्यक्रमों में 500 से अधिक अधिकारियों/विकासकों ने भाग लिया।

प्रक्रिया प्रवाह तथा टीए से सहायता

पुनर्वित्त विभाग द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों/प्रक्रियाओं का सम्पूर्ण इकोसिस्टम एवं क्रिस्टा द्वारा दी गई सहायता;

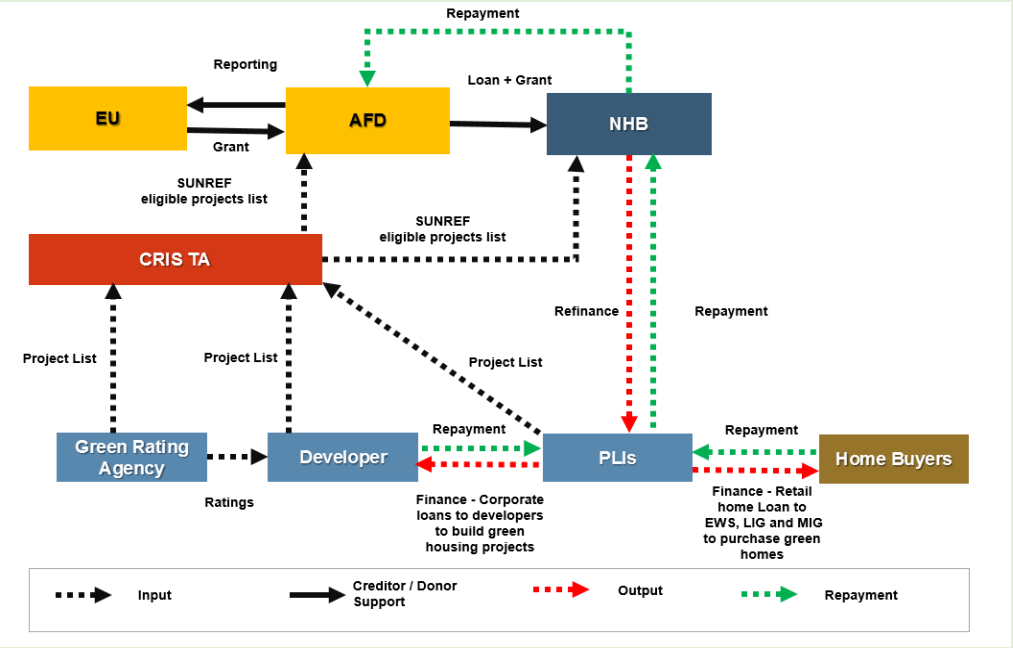

फोटो गैलरी

कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें नीचे दी गई है:

श्री एस के होता - प्रबंध निदेशक, रा.आ.बैंक दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को आयोजित सनरेफ कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

दिनांक 21 फरवरी, 2020 को आयोजित सनरेफ प्रचार कार्यक्रम में ईयू, एएफडी तथा रा.आ.बैंक के अधिकारी

एएफडी तथा रा.आ.बैंक के अधिकारी दिनांक 21 फरवरी, 2020 को मुंबई में आयोजित सनरेफ क्षेत्रीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

रा.आ.बैंक के अधिकारी प्रतिभागियों को रा.आ.बैंक की सनरेफ पुनर्वित्त योजनाओं के बारे में समझाते हुए

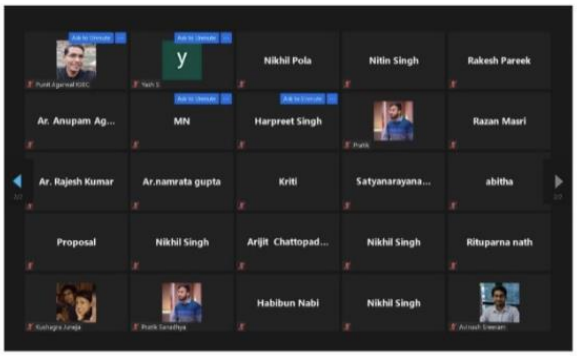

Sunref
INDIA
Training Session for Developers
“Green Affordable Housing”
September 04, 2020
Developed by
AFD
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
With financial participation of
EUROPEAN UNION
Implemented by
राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

IGBC Residential Projects
Haryana
Rajasthan
Uttar Pradesh
Assam
Gujarat
Maharashtra
West Bengal
Telangana
Andhra Pradesh
Karnataka
Tamil Nadu
Registered : 2,218
Pre-Certified : 1,063
Certified : 290
Participants (57)

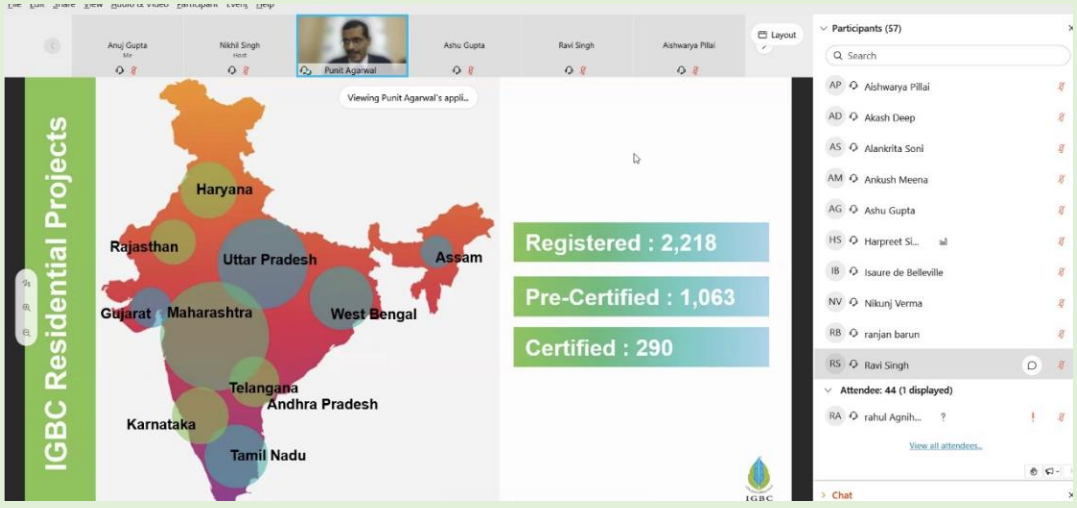

प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों हेतु वेबिनार

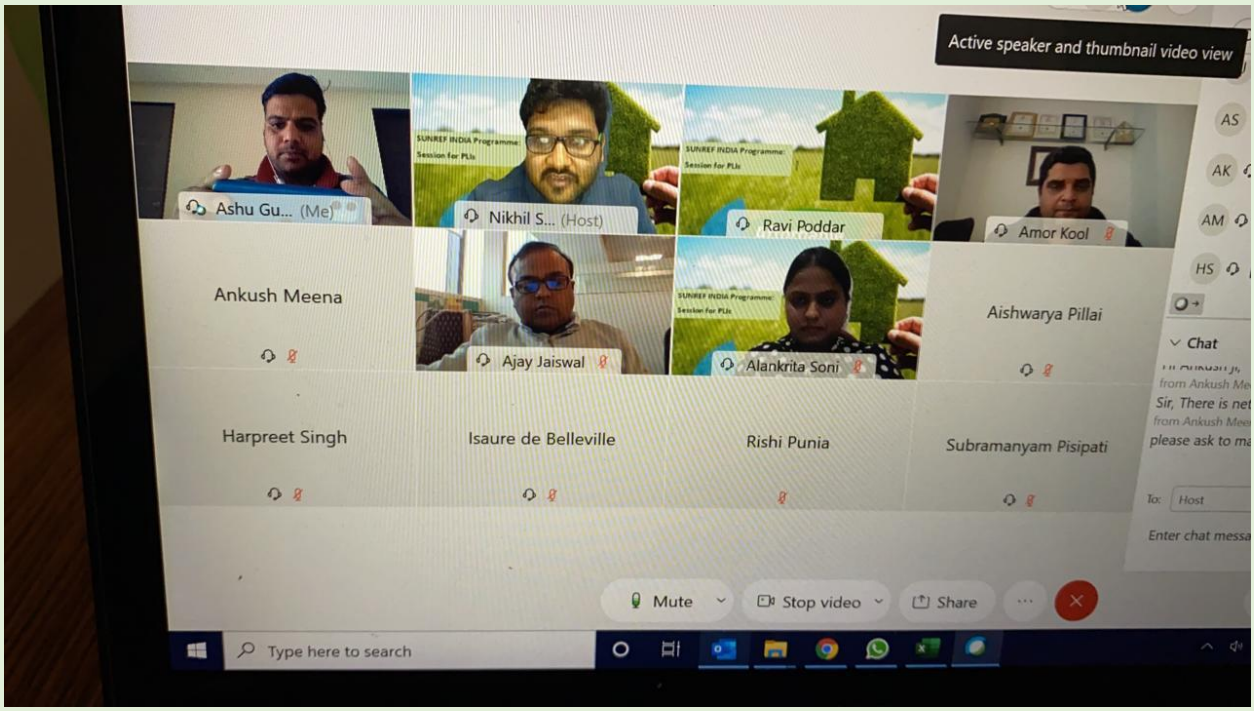

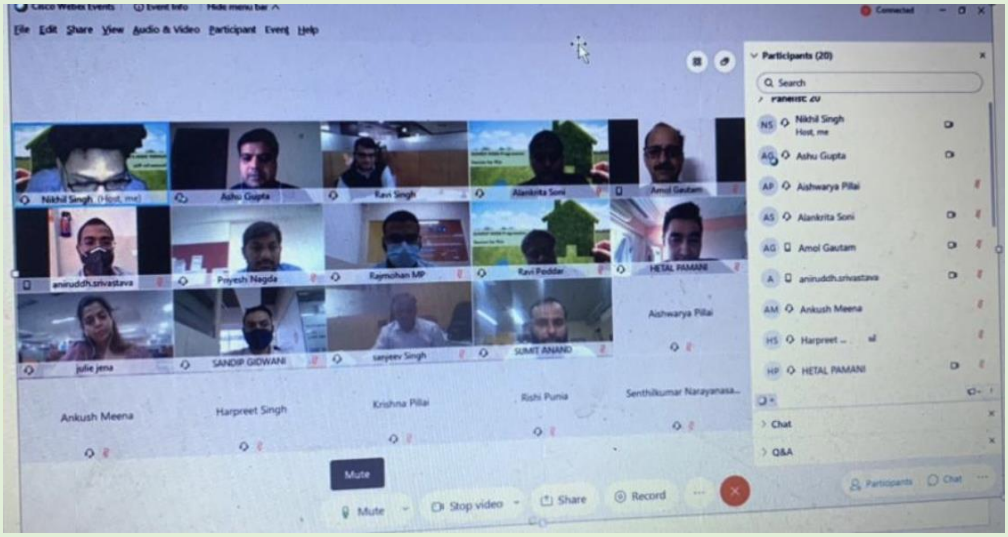

प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों हेतु वेबिनार

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु प्रशिक्षण सत्र

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड हेतु प्रशिक्षण सत्र

हमसे संपर्क करें

कार्यक्रम, पुनर्वित्त योजनाओं एवं आवेदन प्रक्रियाओं आदि के संबंध में अधिक जानकारी हेतु कृपया संपर्क करें:

राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
फ़ोन 011-39181065
ईमेल - nhbho@nhb.org.in

संबंधित अधिकारीः राष्ट्रीय आवास बैंक से श्री रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक (मो.- 9717691296), श्री. सुभाष, क्षेत्रीय प्रबंधक (मो.- 8155878644) तथा क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड से श्री मुकुल दिक्षित (मो-9560704941), श्री. निखिल (मो.- 9810407631) से संपर्क किया जा सकता है।

x-x-x